(e) whether there is any likelihood of decrease in the prices of sugar in the open market consequent upon the excess sugar production in the country?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) The production of sugar during 1994-95 season was 145.85 lakh tonnes (Provisional) against the total installed production capacity of 122.1970 lakh tonnes as on 30-9-1995 showing a production of 23.653 Lakh Tonnes in excess of the installed capacity.

(c) The production of sugar during 1994-95 sugar reason was higher in the States of Uttar Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Pondicherry and Goa than their installed sugar production capacities as on 30-09-1995.

(d) No further import of sugar is contemplated on Government Account at present.

(e) The free-sale sugar release mechanism is being regulated in a judicious manner in order to maintain the prices of sugar in the open market at reasonable level to the consumers as well as the producers to enable them to pay remunerative cane prices to the fanners.

चावल निर्यात में घोटाला

1142. **श्री ओ.पी. कोहली** :

श्री जनेश्वर मिश्र:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 फरवरी 1996 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "फूड मिनिस्ट्री, एफ.सी.आई. एंड बिक गनज़ फेवरिंग राइस एक्सपोर्टर्ज़" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि निर्यातकों को कई करोड़ रूपयों का लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर पारेषण का मूल्य कम करते हुए खाद्य मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम के शीर्षस्थ अधिकारियों के स्तर पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है और चावल की कीमत कम करके जिन निर्यातकों को लाभ पहुंचाया गया है उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां * । सरकार को इस समाचार के सम्बंध में जानकारी है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि उन्होनें सक्षम प्रधिकारियों द्वारा समय-समय पर यथाअनुमोदित मूल्य नीति के अनुसार निर्यात के लिए चावल की ब्रिकी की है । उच्च स्तरीय समिति द्वारा इस समय पंजाब मे निर्यात मूल्य जानबूझकर अधिक निर्धारित किए गए थे । ताकि खरीददार/मिलमालिक स्टाक को "लेवी चेनल" में पुनः न भेज (रिसाइकलिंग) सकें । प्रथम दृष्टाया समाचार में निर्दिष्ट आरोप सही नहीं है ।

उन चावलों निर्यातकों, जिन्हें चावल की सुपुर्दगी दी गई थी, की सूची विवरण में दी गई है ।

विवरण

प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के उन खरीदारों की सूची जिन्हें निर्यात के प्रयोजन के लिए चावल बेचा गया था

1. भारतीय राज्य व्यापार निगम
2. खनिज तथा धातु व्यापार निगम
3. प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफॅ इंडिया लिमिटेड
4. मै. हमदन एक्सपोर्टर्स
5. मै. निर्मल कुमार भूरा एंड कम्पनी
6. मैं. बिशन सरूप राम किशन
7. कुन्दन राइस मिल्स
8. एल.टी. ओवरसीज़
9. मैं बी.एस.आई. लिमिटेड
10. मै. एस.एच.ग्रुप
11. मै. तन्ना एग्रो एम्पेक्स
12. मै. कोठारी ग्लोबल
13. मै. जिन्दल निर्यात
14. मै. सम्पात इंडस्ट्रियल कन्स. कम्पनी
15. मै. कोटक एण्ड कम्पनी
16. मै. टीना ऑयल एण्ड कैमिकल्स
17. मै. श्री रायर इम्पेक्स
18. कान्तिलाल एंड कम्पनी
19. मै. वी.के.एजेन्सीज़
20. तोराई ओवरसीज़ लिमिटेड
21. अनन्त त्रफीना
22. मै. सचदेवा एण्ड सन्स

23. जिन्दल ओवरसीज़ लिमिटेड
24. शिवम इण्टरनेशनल
25. मै. नोवाकॉम ऑयल प्रोडक्ट
26. खुशीराम बिहारीलाल
27. एम.बी.एक्सपोर्ट्स
28. पुन्सुप (पंजाब राज्य नागरिक निगम)
29. रामा एसोसिएट्स
30. प्रियंका ओवरसीज़
31. टीना ओवरसीज़ लिमिटेड
32. जमनादास माधवजी
33. शिवानाथ राय हरनारायण
34. अल्लानासन्स
35. ताना ट्रेडिंग कार्पोरेशन
36. मै. रघुनाथ इण्टरनेशनल
37. यूनीवर्सल एण्टरप्राइज़ेज़
38. सतनाम आवेरसीज़ लिमिटेड
39. मै. एमसन्स लिमिटेड
40. मै. स्पेस एण्टरप्राइजेज़
41. मै. आर. प्यारेलाल इण्टरनेशनल.
42. मै. मुंमार्क
43. मै.श्रीजी ट्रेडिंग कम्पनी
44. नेफेड (मै. नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन)

Representations received by DGFT

1125. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the details of representations received during the last three months by the DGFT and Government regarding payment of CCS as sanctioned, due and payable prior to 2nd July, 1991;

(b) whether it is a fact that despite clearance in some cases by the DGFT for payment of such CCS amount to the exporters mostly in public sector have not been paid in effect;

(c) whether Government had desired dropping of technical objections raised by Audit Department;

(d) whether the payments has been withheld despite repeated reminders; and

(e) if so, the steps to be taken for making the payment of CCS finally?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI [» CHIDAMBARAM): (a) and (b) Out of the ten representations received in this regard during the last 3 months by the Ministry of Commerce/DGFT in two cases CCS was initially sanctioned and paid but subsequently recovered/adjusted on account of objections raised by the audit. One of the cases related to a Public Sector Company (M/s Bamicr Lawns & Co. Ltd., Cochin).

(c) to (e) The objections raised by the Audit were examined and were accepted by the Government. As such, the question of repayment of the recovered amounts to these firms does not arise.

Census of Families living below the poverty threshold

1126. SHRI MD. SALIM:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased lo state:

(a) the total number of families in India according to the 1991 census;

(b) the total number of families who were living below the poverty threshold in June, 1991;

(c) the total number of familiies living below the poverty threshold at the end of 1994-95 fiscal year as well as the latest available data on this; and

. (d) the definition of poverty threshold in terms of family income per annum?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLMENTATION (SHRI BALARM SINGH YADAV): (a) As per 1991 Census there were 152,009,467 households in India (excluding Jammu & Kashmir where the 1991 Census was not held).

(b) and (c) The Planning Commission estimates number of persons below poverty line on the basis of quinquennial survey on Household Consumer